जन connect

सत्यमेव जयते

मोदी सरकार के 50 दिन

निर्णायक और दिशासूचक

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

बजट 2019 - 50 खरब अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था की बुनियाद

सबको शक्ति, सबका विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2019-20 से 2021-22 की अवधि में ग्रामीण भारत के पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

2022 तक, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास बिजली का कनेक्शन हो और स्वच्छ ईंधन के लिए रसोई गैस की व्यवस्था हो।

जल-जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेय जल की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान-धन योजना नाम की नई योजना के अतंर्गत 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी।

समाज कल्याण के लक्ष्यों के लिए काम कर रहे सामाजिक उद्यमों और स्वयं सेवी संगठनों को सूचीबद्ध करने और इलेक्ट्रानिक रूप में धन जुटाने के मंच के रूप में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज़ स्थापित किया जाएगा।

सस्ते मकानों को और बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च, 2020 तक खरीदे जाने वाले 45 लाख रुपये मूल्य तक के मकानों पर लिए गए ऋण पर अदा किए गए 1.5 लाख रुपये तक ब्याज पर आयकर में अतिरिक्त छूट।

परंपरागत उद्योगों के उन्नयन और पुनर्गठन के लिए वित्तपोषण कार्यक्रम (स्फूर्ति) के अतंर्गत 2019-20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 50 हजार कामगार आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल हो सकेंगे।

प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में मुद्रा ऋण के अंतर्गत एक महिला को 1 लाख रुपये तक के ऋण की अनुमति होगी। वैध जन-धन खाता रखने वाली स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को 5 हजार रूपये तक ओवर ड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी।

व्यापार को बढ़ावा

400 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर की दर अब 25 प्रतिशत होगी। पहले ये सुविधा 250 करोड़ रुपये तक कारोबार वाली कंपनियों को ही प्राप्त थी। इस प्रकार देश में मौजूद 99.3 प्रतिशत कंपनियां इसका फायदा उठा सकेंगी।

बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान देने की कार्य योजना के साथ दीर्घावधि बांडों के लिए बाजारों का विस्तार करने के लक्ष्य से वर्ष 2019-20 में ऋण गारंटी संवर्धन निगम (सीजीईसी) की स्थापना की जाएगी।

सभी जीएसटी - पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमईज़) को नए अथवा संवर्धित ऋणों पर ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार विभिन्न श्रम कानूनों को व्यवहारिक और तर्कसंगत बनाने के लिए उन सबको 4 श्रम संहिताओ (कोड्स) में समाहित करने के प्रयासों में तेजी लाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते 'स्टैंड अप इंडिया' योजना 2025 तक जारी रहेगी।

किसानों की आय दोगुनी करना

खेती के परंपरागत तरीकों को फिर से अपनाने के लिए शून्य खर्च खेती अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए जाएंगे। ये संगठन किसानों को एकजुट करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि कृषि सुधारों के लाभ किसानों तक अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।

ये कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओज़) छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट करेंगे ताकि वे कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकें और अपनी उपज को ऊंचे मूल्यों पर बेच सकें।

कृषि-ग्रामीण उद्योंगो में 75,000 प्रशिक्षित उद्यमियों के विकास के लिए एएसपीआईआरई कार्यक्रम के अतंर्गत 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे।

सरकार मत्स्य उद्योग क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देगी।

बुनियादी ढांचे और निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित करना

अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दीर्घावधि के निवेश पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

रेलवे के ढांचे में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। यात्री और माल भाड़ा सेवाओं का तीव्र विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया जाएगा।

सरकार देश में बेहतर संचार और ढांचा विकास के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इनमें निम्नांकित कार्यक्रम शामिल हैं:

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
2. औद्योगिक गलियारे
3. प्रतिबद्ध माल ढुलाई कारीडोर
4. भारत माला
5. सागर माला
6. जल मार्ग विकास
7. उड़ान कार्यक्रम

सरकार एफडीआई का प्रवाह बढ़ाने के लिए मीडिया, एनिमेशन और कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार करेगी।

बीमा बिचौलिया कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाएगी।

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जुटाने के वास्ते स्थानीय स्रोत मानदंड आसान बनाए जाएंगे।

वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) को माध्यम बनाते हुए प्रमुख वैश्विक कंपनियों को भारत आने और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भारतवंशियों का कल्याण

अब भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत पहुँचने पर आधार कार्ड जारी किया जाएगा, इसके लिए उन्हें अब 180 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अप्रवासी भारतीयों को इंडियन इक्विटी तक सहज पहुंच प्रदान करने के लिए एनआरआई-पोर्टफोलियो निवेश योजना को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से विलय किया जाएगा।

बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर रिज़र्व बैंक का नियामक प्राधिकार सुदृढ़ किया जाएगा और एनएफसीज़ को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के अंतर्गत सीधे भाग लेने की अनुमति देने के उपाय किए जाएंगे।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की छूट दी गई है।

चुने हुए केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के कार्यनीतिक विनिवेश को प्राथमिकता देना जारी रखा जाएगा। एयर इंडिया के कार्यनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।

शिक्षा और युवाओं को अधिक शक्ति

खिलाड़ियों के विकास के लिए 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (एनएसईबी) की स्थापना की जाएगी।

भारत को उच्चतर शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने 'भारत में अध्ययन' नाम का कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिससे विदेशी विद्यार्थियों को 'भारत में अध्ययन' करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकार आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा, रोबोटिक्स तथा तकनीक के अन्य नए क्षेत्रों में युवाओं का कौशल सुधारने के उपायों को और बढ़ावा देगी।

प्रवासी भारतीयों को भारतीय शेयर बाज़ार में निर्बाध निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश योजना को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश योजना में समाहित किया जाएगा।

देश में समग्र अनुसंधान प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार सभी मंत्रालयों के अंतर्गत उपलब्ध धन को एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगी।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) विभिन्न अतंरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का प्रसार करेगी।

पर्यटन

सरकार 17 विख्यात पर्यटन स्थलों का विकास विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में करेगी ताकि इन पर्यटन स्थलों पर घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ायी जा सके।

पहले ही दिन से लक्ष्य की ओर अग्रसर

चिकित्सा शिक्षा सुधार

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए है। यह क्षेत्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है ।

इस कदम से देश में चिकित्सा शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता आएगी, साथ ही जवाबदेही और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 25 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2,750 सीटें

MAMMOMAT Inspiration

जम्मू और कश्मीर में विकास और विश्वास

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत देने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इन क्षेत्रों के लोग अब सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

यह अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है।

गृह मंत्री की जम्मू-कश्मीर यात्रा ऐतिहासिक रही है। इस यात्रा में जहां शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, वहीं अलगाववादी तत्वों को दरकिनार किया गया।

Business Standard

Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill passed in Lok Sabha

ANI | Politics

Last Updated at June 28, 2019 16:45 IST

एक भयावह कुप्रथा के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का साथ

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 मुस्लिम महिलाओं को उनका मूलभूत अधिकार दिलाने और अन्याय दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है ।

यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके पतियों द्वारा 'तलाक-ए-बिद्दत' जिसे सामान्यतः तीन तलाक कहा गया है, के जरिए तलाक देने की कुप्रथा को रोकने में मदद करता है।

अमर उजाला

होम | देश | शहर और राज्य | टेक | ऑटो | ज्योतिष | वीडियो | मनोरंजन

Home › India News › Union Cabinet Approves Triple Talaq Bill

तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, आगामी संसद सत्र में पेश करेगी सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 12 Jun 2019 07:50 PM IST

Don't Link Triple *Talaq* Bill "To Any Community", PM Warns Congress

Accusing the Congress of missing ground realities because it "flies high", the PM Modi said it missed the opportunity in the '50s to establish a uniform civil code and "instead, went ahead with the Hindu Code Bills"

Edited by Anindita Sanyal | Updated: June 26, 2019 09:52 IST

जम्मू-कश्मीर में शरारती तत्वों को नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक कदम

जम्मू-कश्मीर बैंक में हुए भ्रष्टाचार पर चोट उन लोगों के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश है, जिन्होंने पिछले तीन दशकों से कश्मीर घाटी और जम्मू-कश्मीर की राजनीति को अपने नफरत के एजेंडे से बंधक बना रखा था।

जम्मू-कश्मीर बैंक अलगाववादियों से लेकर वंशवाद-आधारित राजनीतिक दलों तक, ऐसे कपटी लोगों का अड्डा बन चुका था जो कश्मीर को अशांत बनाए रखना चाहते थे।

लोगों का मानना था कि इस बैंक में संदिग्ध लेनदेन हो रहे थे और असामाजिक तत्वों के लिए यह धन जुटाने का एक आसान जरिया बन गया था।

बैंक के खिलाफ कार्रवाई से पारदर्शिता आई और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। यह एक ऐसा कदम है जिससे राज्य में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

THE ECONOMIC TIMES

Clean-up signals a shift, hurts old consensus in Jammu Kashmir

BY PRANAB DHAL SAMANTA, ET BUREAU | UPDATED: JUN 11, 2019, 09.38 PM IST

The crackdown on Jammu & Kashmir Bank is more than just punching holes in the records of a recalcitrant financial institution. It's a strong political message to Srinagar that Delhi will leave no stone unturned to wreck the consensus which has run the city, the Valley and its politics for the past three decades.

जनता के धन के दुरुपयोग की कुप्रवृत्ति पर अंकुश

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 से सरकारी परिसरों के मकानों में अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

इससे सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को तेजी से बेदखल किया जा सकेगा।

गगनयान, चंद्रयान –२ से लेकर सूर्य और शुक्र पहुंचने का अभियान

गगनयान - 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक भारत द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान।

चंद्रयान -2 मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने में मदद करेगा और चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा। इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई, 2019 को किया गया।

सौर मिशन आदित्य एल 1 का प्रक्षेपण 2020 में निर्धारित है। यह सूर्य के कोरोना और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा।

मिशन टू वीनस - 2023 में प्रस्तावित इस अभियान का उद्देश्य शुक्र के वातावरण और सतह की आकृति का अध्ययन करना है।

ईएसआई सुधारों से अनुपालन की सरलता और कारोबार करने की आसानी

- मोदी सरकार ने नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों, दोनों से ईएसआई योगदान दर को घटाया।
- नियोक्ताओं के योगदान को 4.75% से घटा कर 3.25% किया गया।
- कर्मचारियों के योगदान को 1.75% से घटा कर 0.75% किया गया।
- इससे 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 नियोक्ताओं को लाभ पहुंचा।
- इससे श्रमिकों को उल्लेखनीय आर्थिक लाभ हुआ, नियमानुरूप कार्य करने को बढ़ावा मिला और ईएसआई योजना में श्रमिकों का अधिक नामांकन किया जाना सुगम हुआ।

हवाई अड्डों को पट्टे पर देकर राजस्व में वृद्धि और उनके स्तर में सुधार

मोदी सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलूरू स्थित तीन हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से पट्टे पर देने का फैसला किया।

इन परियोजनाओं से आवश्यक निवेश के साथ-साथ सेवा प्रदान करने, निपुणता, उद्यमिता और व्यावसायिकता में सुधार होगा।

इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ टीयर दो और टीयर तीन शहरों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा और निवेश करने में मदद मिलेगी। ऐसी विकासात्मक गतिविधियों से इन शहरों में रोजगार बढ़ाने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के बहादुर कार्मिकों को अधिक लाभ

ZEE BUSINESS हिंदी में पढ़ें

INDIA WORLD COMPANIES PERSONAL FINANCE MUTUAL FUNDS TECHNOLOGY AUTOMOBILE SMALL BUSINESS

Home » India News

Paramilitary officers' promotion: Modi Cabinet clears proposal for Central Armed Police Forces (CAPF); check other decisions

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बहादुर अधिकारियों के संवर्ग स्तर में वृद्धि को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इससे इन बलों के अधिकारी गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफ) सहित अन्य लाभों के पात्र हो जाएंगे।

- इस प्रस्ताव से पांच मूलभूत सीएपीएफ अथवा अर्द्धसैनिक बलों-सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के हजारों सेवारत अधिकारियों और 2006 के बाद सेवानिवृत हुए अनेक कार्मिकों को लाभ पहुंचा है।

- ये अधिकारीगण बेहतर प्रतिनियुक्ति के अवसर प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि वे केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे, उन्हें बढ़ी हुई परिवहन सुविधाएं, मकान किराया भत्ता और परिवहन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।

रेलवे सुरक्षा बल को संगठित समूह 'ए' का दर्जा

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को संगठित समूह 'ए' का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रेलवे सुरक्षाबल (आरपीएफ) को संगठित समूह 'ए'का दर्जा देने से पात्र अधिकारियों के तरक्की के अवसर बढ़ेंगे।

अधिकारियों के तरक्की के अवसरों में सुधार से उन्हें प्रेरित रखने में मदद मिलेगी।

इससे नतीजतन गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफएफयू) के अवसर भी बढ़ेंगे।

ग़रीबों को वित्तीय धोखाधड़ियों से बचाना

मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजना विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान की।

इसमें कारोबार के साधारण व्यवसाय में जमाराशियों को छोड़ कर अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा गतिविधियों के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में कानूनी त्रुटियों तथा ढीली प्रशासनिक व्यवस्था का फायदा उठाकर गरीब लोगों की मेहनत की पूंजी को हड़प जाती हैं।

अंतर्राज्यीय जल विवादों का दक्षतापूर्वक समाधान

मोदी सरकार ने अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी।

इस विधेयक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान तंत्र तथा वर्तमान संस्थागत व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की गई है।

केवल एक ही अधिकरण (ट्रायब्यूनल) की स्थापना से - जो विभिन्न पीठों के जरिये कार्य करेगा तथा फैसला सुनाने संबंधी समय सीमा तय कर देने से विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा

ख़रीफ़ की फ़सलों के लिए ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य

आर्थिक मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति द्वारा खरीफ फसलों के लिए अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किसानों को उनकी उत्पादन लागत की 1.5 गुणा धनराशि उपलब्ध कराने के अनुरूप है।

किसानों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की उच्चतम दर बाजरा (85 प्रतिशत), उड़द (64 प्रतिशत) और तुअर (60 प्रतिशत)में है।

Cabinet approves higher minimum support prices for Kharif crops

BY ET BUREAU | UPDATED: JUL 04, 2019, 07.48 AM IST

श्रम कानून में सुधारों के फलस्वरूप असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों को लाभ

- मोदी सरकार द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान की गई।
- 10 या अधिक कामगारों वाली किसी भी व्यावसायिक निकाय के लिए अपने सभी कामगारों को नियुक्तिपत्र जारी करना और वार्षिक आधार पर डॉक्टरी जांच कराना अनिवार्य होगा।
- साथ ही महिलाएं रात की शिफ्ट में स्वेच्छा से काम करने का विकल्प दे सकती हैं।
- इससे सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के प्रावधानों का सुधार होगा ।
- नये विधेयक में शिशु देखभाल (क्रेच), कैंटीन, फर्स्ट ऐड, कल्याण अधिकारी से जुड़े प्रावधानों को एकसमान बनाने की व्यवस्था की गई है।
- इस विधेयक में न केवल कामगारों के लाभ बल्कि फर्मों के लिए काम की सुगमता को भी सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें एक प्रतिष्ठान के लिए एक पंजीकरण का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में 13 अधिनियमों में से छह श्रम अधिनियमों में अलग-अलग पंजीकरण की व्यवस्था है।
- इस विधेयक में अनेक लाइसेंसों के स्थान पर एक ही लाइसेंस तथा एक ही रिर्टन का प्रावधान किया गया है और वर्तमान 13 श्रम कानूनों को श्रमसुधारों में समायोजित कर दिया गया है।
- एक लाइसेंस और एक रिर्टन के फलस्वरूप प्रशासन को समय, संसाधन और प्रयासों की बचत होगी।

करोड़ों कामगारों के हित में श्रम सुधार

मोदी सरकार ने श्रम मजदूरी संहिता विधेयक को पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए केंद्र को सक्षम बनाने के उद्देश्य से मंजूरी प्रदान की है।

इससे चार वर्तमान श्रम कानूनों के प्रावधान संयोजित हो जाएंगे तथा सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानूनी प्रावधानों की छत्रछाया मिल सकेगी ।

इससे करीब 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा क्योंकि उन सभी को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा - फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र में या वेतन-स्तर पर कार्यरत हों ।

इससे कारोबार की सुगमता भी सुनिश्चित होगी। इसमें 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 सरल किया गया है। इस समय अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की न्यूनतम मजदूरियां हैं। ये संहिताएं उन्हें सरल बना सकेंगी ।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा

सरकार ने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम, 2012 में किये गये ये संशोधन इसे और सुदृढ़ बनाते है। बच्चों के प्रति यौन अपराध करने वालों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया हैं।

इन संशोधनों में बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए आर्थिक दंड लगाना और कारावास की सजा भी शामिल है।

अधिनियम में शामिल सख्त दंडात्मक प्रावधानों के कारण बच्चों के यौन शोषण पर प्रभावकारी ढंग से अंकुश लगने की उम्मीद है।

अवसंरचना को भरपूर बढ़ावा – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – III

- पीएमजीएसवाई-II, जिसने ग्रामीण सड़क निर्माण की गति दोगुनी की और बड़े पैमाने पर भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क को बढ़ाया, की व्यापक सफलता के बाद पीएमजीएसवाई-III घोषित की गई है
- पीएमजीएसवाई-III में ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों के जरिये आबादी वाले इलाकों को जोड़ते हुए रास्तों और प्रमुख ग्रामीण मार्गों को और प्रभावकारी बनाना है ।
- पीएमजीएसवाई-III के तहत 1,25,000 किमी. सड़क लंबाई को तर्कसंगत बनाना तथा बिना संपर्क वाले गांवों और आबादी से जुड़े इसके रास्तों को विकास का प्रमुख साधन बनाना है ।

दिवालियापन कोड को और मजबूत बनाने कि लिए संशोधन

दिवालियापन कोड (आईबीसी) में अनेक संशोधनों को मंजूरी दी गई है।

यह गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का तेजी से समाधान करने के लिए व्यवस्था को और मजबूत बनाता है ।

राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण (एनसीएलटी) में लाए गए एनपीए के समाधान की समय सीमा 330 दिन तय की गई है, जिसमें कानूनी चुनौतियों में बिताया गया समय शामिल है।

ये संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि बड़े ऋणदाताओं और ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा निर्धारित समाधान योजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाए ।

संभावित समाधान की दिशा में सीओसी अब एन पी ए की पुनर्संरचना अधिग्रहण, विलय और विभाजन का निर्णय कर सकती है।

सरकार घर खरीदने वालों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ी है। ऐसे खरीददार अचल संपत्ति क्षेत्र के ऋणदाताओं का काफी बड़ा भाग है। ऐसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधित्व के अधिकारों के लिए नए सिरे से काम किया गया है जो मतदान के दौरान हो सकता है उपस्थित न हों। मतदान के दौरान आधे से अधिक उपस्थित लोगों द्वारा व्यक्त मत को ऋणदाताओं द्वारा समाधान योजना के पक्ष अथवा विपक्ष में शत-प्रतिशत मत माना जाएगा।

पुराने पड़ चुके 58 कानूनों को समाप्त करना

2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1,000 से ज्यादा अनुपयोगी कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब 2019 में सरकार ने 58 अन्य अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है।

इनमें से कुछ कानून बड़े पुराने थे लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए इनका दुरुपयोग किया जा सकता था।

गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर – एलपीजी के दामों में कटौती

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दरों में कमी की पृष्ठभूमि में गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी के मूल्य में प्रति सिलेंडर 100 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है।

दिल्ली में रसोई गैस का दाम 637 रुपये प्रति सिलेंडर होगा जबकि इससे पहले इसका दाम 737.50 रुपये था।

भगौड़ों तक पहुंचे कानून के लंबे हाथ

प्रवर्तन निदेशालय ने स्टरलिंग बायोटेक की 9,778 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। निदेशालय ने एसबीएल समूह, संदेसारा बंधुओं और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा 5,700 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दायर करने के बाद इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

इस बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने भगौड़े धोखेबाज मेहुल चोकसी के बारे में कुछ इस प्रकार कहा : "उसकी (चोकसी) नागरिकता की अर्जी पर कार्रवाई की गई थी; और वह मंजूर भी हो गई, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा और उसे वापस भारत भेज दिया जाएगा।"

INDIA TODAY

Antigua PM says Choksi to be extradited after court nod

According to sources, the diplomatic pressure mounted by India on the issue has played a crucial role in the Caribbean nation accepting the fact that Mehul Choksi has to be deported. The Prime Minister of Antigua has said it is not a case that "we are trying to provide any safe harbour to criminals and those who are involved in financial crimes".

समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे विकास

उज्ज्वला योजना के ऐसे लाभान्वितों के लिए 5 किलोग्राम के एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरु किया गया जो बड़े रिफिल नहीं खरीद सकते। पांच किलोग्राम के रिफिल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में विशेष शिविर आयोजित किए गए।

अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी पहल के तहत वहां बाढ़ से निपटने के एक प्रयास के साथ एक बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना को मंजूरी। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2,880 मेगावाट है।

जन शिक्षा संस्थानों में कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ करना ताकि समाज के ऐसे वर्गों तक कौशल का लाभ पहुंच सके जो सुविधाओं से वंचित हैं।

सरकार ने एक विधेयक पेश करने के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें 'ट्रांसजेंडर्स' को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाने की व्यवस्था है।

मजबूत सरकार, मजबूत संसद

पिछले कुछ वर्षों की तुलना में पहली बार 2019 में संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान बिना किसी बाधा के कामकाज हुआ।

सत्र के दौरान 17 विधेयक पारित किए गए। 104 नए विधेयक पेश किए गए।

यह जनता के जनादेश से बनी मजबूत सरकार का प्रभाव है।

उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

संसद में नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पेश किया गया जिसमें उपभोक्ता विवादों का समय पर निपटारा करने के साथ ही उपभोक्ता अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह वर्तमान कानून का दायरा बढ़ाता है ताकि दूरसंचार और आवास निर्माण सहित सभी वस्तुओं और सेवाओं को तथा लेनदेन के सभी स्वरूपों (ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग आदि) को इसके तहत लाया जा सके।

किए हुए वादों पर अमल

सरकार का पहला निर्णय देश के सरक्षा प्रहरियों को समर्पित

01 सरकार के पहले निर्णय से ही पता चल गया था कि देश की सुरक्षा में अपना जीवन अर्पित करने वाले उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

02 राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई। छात्रवृत्ति की राशि में काफी वृद्धि की गई।

03 इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना के दायरे को बढ़ाया गया। आतंकवादी या नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए राज्यों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया।

In His First Decision, PM Modi Hikes Scholarships For Wards Of Armed Forces, Extends It To Police

The rates of scholarship have been increased from Rs. 2000 per month to Rs. 2500 per month for boys and from Rs. 2250 per month to Rs. 3000 per month for girls, the Prime Minister's Office said in a statement.

OUTLOOK WEB BUREAU | 31 MAY 2019

मोदी कैबिनेट में पहला फैसला: नेशनल डिफेंस फंड के तहत स्कॉलरशिप बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में ट्वीट किया है और लिखा है कि हमारी सरकार का पहला फैसला उनके लिए है जो राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं. नेशनल डिफेंस फंड के तहत प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है.

अन्नदाताओं का जीवन सुरक्षित करने के लिए पेंशन योजना

- स्वैच्छिक और अंशदायी (Contributory) पेंशन योजना के माध्यम से 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना।
- केंद्र सरकार किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए 3 वर्षों के दौरान अपनी तरफ के अंशदान पर लगभग 10,774.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- इस योजना में किसानों को यह विशेष सुविधा दी गई है कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में से अपना अंशदान हर महीने सीधे इस योजना में दे सकते हैं।

Bonanza to farmers in first Cabinet; govt extends PM-KISAN, announces new farm pension scheme

Govt also okayed Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana under which farmers will get pension of Rs 3,000/month.

PTI | Updated: May 31, 2019, 09.09 PM IST

आज तक

न्यूज़ सिनेमा फोटो वीडियो गैजेट्स जुर्म फैक्ट चेक •LIVE TV

Hindi News / लाइव ब्लॉग

Feedback

किसानों और छोटे व्यापारियों को मोदी सरकार की सौगात

मोहित पोवर 02 जून 2019, अपडेटेड 00:25 IST

आखिरकार तीन महीने की चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सरकार का गठन हो गया है. गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली, उनके समेत कुल 58 मंत्रियों ने शपथ ली है. इसमें कुल 25 कैबिनेट मंत्री हैं (PM समेत) जबकि 9 स्वतंत्र प्रभार, 24 राज्य मंत्री शामिल हैं. शपथ के साथ ही पीएम ने काम भी शुरू कर दिया है, इसके अलावा सभी मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा भी हो गया है.

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

पीएम–किसान का लाभ सभी किसानों को

- पीएम-किसान योजना के तहत अब सभी किसान परिवारों को शामिल कर लिया गया है – चाहे उनकी खेती का आकार कुछ भी हो।
- इस विस्तार से अब इस योजना का लाभ और 2 करोड़ किसानों को मिलेगा।
- इस प्रकार, अब पीएम-किसान योजना का लाभ 14.5 करोड़ लोगों को मिलने लगा है।
- अब तक :
- 2,000 रुपये पहली किस्त 3.11 करोड़ किसानों को जारी कर दी गई है।
- 2000 रुपये की दूसरी किस्त 2.66 करोड़ किसानों को दे दी गई है।

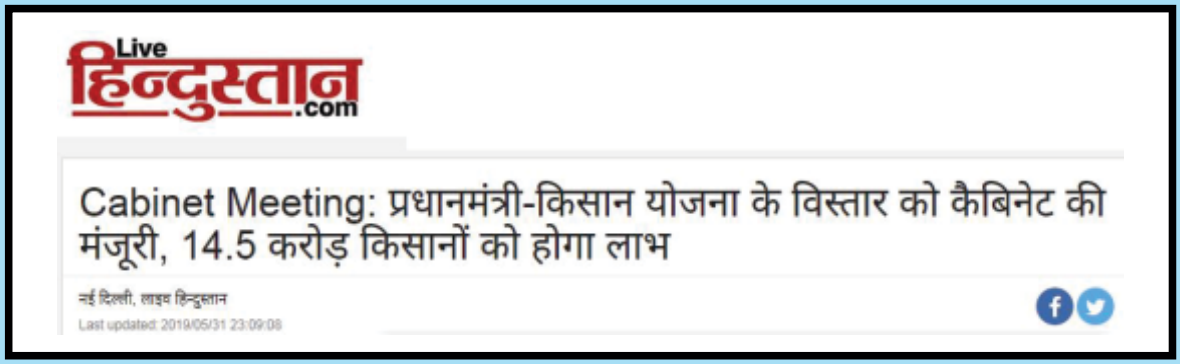
Live हिन्दुस्तान .com

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री-किसान योजना के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, 14.5 करोड़ किसानों को होगा लाभ

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

Last updated: 2019/05/31 23:09:08

व्यापारियों के लिए पेंशन योजना

- मोदी सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जो व्यापारी समुदाय को भी पेंशन कवरेज प्रदान करती है।
- इस योजना से 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार लाभार्थियों के अंशदान के बराबर का हिस्सा बैंक खाते में डालेगी।
- सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

FINANCIAL EXPRESS

मोदी 2.0 ने ट्रेडर्स पेंशन स्कीम पर लगाई मुहर, छोटे दुकानदार व कारोबारी ऐसे पा सकते हैं 3000 रु महीना

BusinessLine

Cabinet approves pension scheme for small shopkeepers, retail traders

Our Bureau | New Delhi | Updated on May 31, 2019 | Published on May 31, 2019

जल शक्ति मंत्रालय का गठन

- अपने संकल्प पत्र और चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए पानी से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहली बार अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इससे जल समस्या का तेज और व्यापक समाधान संभव हो सकेगा।

- जल प्रबंधन और सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जैसे विषय आज सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस मुद्दे पर ध्यान देते रहे हैं।

- 1 जुलाई, 2019 को जल शक्ति अभियान – जल संरक्षण और जल सुरक्षा को समर्पित — का शुभारंभ हुआ। यह अभियान बरसात के दौरान लोगों की भागीदारी से चलेगा तथा इसमें पानी की तंगी वाले जिलों और ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जागरण MENU राज्य चुनें वीडियो

ताज़ा राष्ट्रीय क्रिकेट दुनिया स्पेशल विश्वास.News मनोरंजन पॉलिटिक्स बिजनेस टेक ज्ञान लाइफस्टाइल आम मुद्दे ऑटो Epaper

हिंदी न्यूज़ / पॉलिटिक्स / राष्ट्रीय

Modi 2.0: मंत्रिमंडल गठन के साथ PM ने पूरा किया वादा, पहली बार बना जलशक्ति मंत्रालय

The Indian EXPRESS

After Swachh Bharat, in the pipeline: Jal Shakti, Nal Se Jal for all

Narendra Modi govt's new focus: The scheme 'Nal se Jal' to provide piped drinking water to every household will be a component of the government's Jal Jivan Mission. This was among the primary promises made in the BJP's vision document released in the run-up to the 2019 Lok Sabha elections.

‘मिशन फाइव ट्रिलियन’ यानी 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

- भारत को ‘पांच ट्रिलियन डॉलर’ यानी 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की भाजपा और पीएम मोदी की प्रतिबद्धता संकल्प पत्र का हिस्सा है।
- पीएम मोदी हमेशा अपने वादों पर खरे उतरे हैं और उन्हें पूरा किया है।
- देश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दो अलग-अलग कैबिनेट कमेटी का गठन किया है।
- निवेश एवं आर्थिक विकास से जुड़ी कमेटी और रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित कमेटी, इन दोनों की अगुआई स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
- पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लिए भी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। इस कमेटी के सदस्यों में कई मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कमेटी पता लगाएगी कि कानून में किस तरह के बदलाव की जरूरत है।

अमर उजाला

होम | देश | शहर और राज्य | टेक | ऑटो | ज्योतिष | वीडियो | मनोरंजन

Home › India News › Pm Modi Says The Goal Of New India To Be Completed By 2022

नीति आयोग पांचवी बैठक: मोदी बोले- 2022 तक पूरा करना होगा ‘न्यू इंडिया’ का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Sun, 16 Jun 2019 12:48 AM IST

The Indian EXPRESS

Modi sets up high-level committee for agricultural reforms at NITI Aayog meet

In his inaugural address at the fifth meeting of the Governing Council of NITI Aayog, Modi reiterated the Union Government's commitment to double incomes of farmers by 2022.

जागरण ≡ MENU 📍 राज्य चुनें ⊙ वीडियो

ताज़ा | राष्ट्रीय | क्रिकेट | दुनिया | स्पेशल | विश्वास.news | मनोरंजन | पॉलिटिक्स | बिजनेस | टेक ज्ञान | लाइफस्टाइल | आम मुद्दे | ऑटो | Epaper

हिंदी न्यूज़ / पॉलिटिक्स / राष्ट्रीय

रोजगार पर मोदी सरकार गंभीर, पीएम की अध्यक्षता में समिति गठित

नौकरशाही में भ्रष्टाचार के विरूद्ध व्यापक कार्यवाही

- 12 शीर्षस्थ कर-अधिकारियों से इस्तीफा लिया गया
- 15 सीमा एवं केंद्रीय सीमाशुल्क अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया।
- इन अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, गैरकानूनी और स्रोत से अधिक सम्पत्ति तथा यौनशोषण के आरोप थे।

FINANCIAL EXPRESS

Modi government's twin decisions to sack tainted officers send shock waves through bureaucracy

INDIA TODAY

Modi govt's surgical strike on corruption: 12 top tax officers asked to quit

मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यों की दुनिया भर में तारीफ

विश्व ने माना भारत निरंतर हो रहा है स्वच्छ!

- यूनिसेफ के एक अध्ययन में पता चला है कि मोदी सरकार की 'स्वच्छ भारत' पहल से भूजल के प्रदूषण में कमी आई है।
- खुले में शौच से मुक्त गांवों में मल संबंधी प्रदूषण, भूजल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण और पेयजल प्रदूषण में कमी आई है।
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक बड़े सुधारों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 'खुले में शौच' को कम करने में सफलता पाई है, और 'स्वच्छ भारत' अभियान ने इसे तेज गति प्रदान की है।
- रिपोर्ट में 'स्वच्छ भारत' के प्रभाव पर कहा गया है : 2000 और 2014 के बीच खुले में शौच का आंकड़ा हर वर्ष लगभग 3 प्रतिशत कम हुआ, जबकि 2015 से 2019 तक इसमें हर वर्ष 12 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है!

NEWS18

Swachh Bharat Abhiyan Gets UNICEF Approval, Body Says Mission Reduced Groundwater Contamination

The study launched by UNICEF found that in terms of faecal contamination, non-ODF villages were on average 11.25 times more likely to have their groundwater sources contaminated.

News18.com | Updated: June 6, 2019, 11:25 AM IST

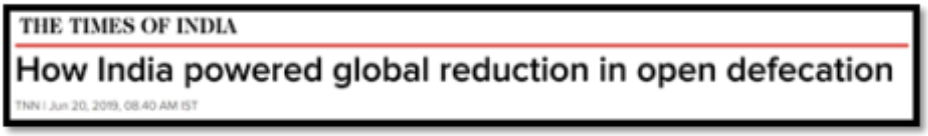
THE TIMES OF INDIA

How India powered global reduction in open defecation

TNN | Jun 20, 2019, 08.40 AM IST

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – भारी प्रभाव वाला व्यापक जन आंदोलन

- जन्म के समय बेटों की तुलना में बेटियों के अखिल भारतीय लिंग-अनुपात में 8 अंकों की वृद्धि हुई और यह 2015-16 की संख्या 923 (प्रति 1000 बालकों की तुलना में) से बढ़कर मार्च 2019 में 931 हो गई।
- हरियाणा में यह संख्या 2015-16 में 887 थी जो 2018-19 में बढ़कर 914 हो गई।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी के लिए मोदी सरकार की विश्वभर में प्रशंसा

- मोदी सरकार में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर व्यापक पैमाने पर कार्य हुए हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से अब लोग कृषि से निकल कर अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं, ऐसे में महिलाएं अब अपने खेतों की देखभाल के लिए घर से बाहर कदम रख रही हैं।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए कहा है कि इससे यातायात में व्यापक सुधार आया है। आर्थिक-व्यापारिक अवसरों तक लोगों की पहुंच बढ़ी है तथा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण सड़कों से जुड़े इलाकों में घरों में होने वाली डिलीवरी की संख्या में भारी कमी आई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बड़ा सुधार माना जा रहा है।

hindustantimes

india icc world cup cities opinion world entertainment mumbai gurugram ht-weekend videos health educa

'Better rural roads led to job opportunities in India': World Bank report

According to the World Bank report, improved road connectivity has "triggered a shift from farm to non-farm employment" and "women stepped out of the house to take care of their farms"

INDIA Updated: Jun 19, 2019 07:04 IST

विश्व–पटल पर भारत का प्रभुत्व

मोदी–2 के 50 दिन

अपनी दूसरी कार्यावधि के पहले 50 दिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत व्यस्त रहे।

पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में BIMSTEC के नेताओं और SCO अध्यक्ष को आमंत्रित किया।

मालदीव का ऐतिहासिक दौरा: पीएम मोदी ने 'मजलिस' को संबोधित किया तथा मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ निशान इजुद्दीन' को ग्रहण किया।

श्रीलंका दौरा:

- पीएम मोदी ने भारत के एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी के साथ एकजुटता दिखाई। वे ईस्टर पर हुए धमाकों के बाद सेंट एंथनी चर्च का दौरा करने वाले पहले विश्व नेता बने।

- पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे और पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे के अलावा तमिल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलनः

- पीएम मोदी ने एससीओ में शामिल देशों के साथ चर्चा की और आतंक के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा।

- किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जेनबेकोव के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की।

पीएम मोदी ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ बैठक की। उनके साथ बातचीत में व्यापार, आतंक और कई अन्य मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया।

जापान में जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व के सभी शीर्ष नेताओं के साथ पीएम मोदी ने व्यापक रूप से चर्चा की।

21 जून को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया।

द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत के पक्ष में जबर्दस्त फैसला सुनाया।

योग दिवस – विश्व पटल पर भारत की आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन

पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व को 170 से अधिक देशों में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान से देश की प्रतिष्ठा में भी भारी वृद्धि हुई है।

इस योग दिवस पर पीएम मोदी ने योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की घोषणा भी की।

जो चार पुरस्कार दिए गए, उनमें इटली की एक महिला और जापान का एक सांस्कृतिक संगठन शामिल है।

FINANCIAL EXPRESS HOME BUDGET 2019 MARKETS STOCKS ECONOMY AUTO INDUSTRY MONEY INDIA INFRA OPINION

UN General Assembly reverberates with chants of 'Om' to mark International Yoga Day

By: PTI | Published: June 21, 2019 1:11:55 PM

The audience actively participated in the yoga sessions and did not let them being seated in one place - as opposed to doing yoga in the outdoors - act as a deterrent.

अमर उजाला

होम देश शहर और राज्य विश्व कप टेक ऑटो ज्योतिष वीडियो

Home › India News › 172 Countries Across World Ready To Celebrate International Yoga Day On 21 July 2019

दुनिया के 172 देशों में एक साथ किया जाएगा योग, ऐसे हो रही है योग दिवस की तैयारी

अमित शर्मा, नई दिल्ली Updated Thu, 13 Jun 2019 06:10 PM IST

मालदीव से रिश्तों में नई घनिष्ठता

पीएम मोदी ने नई सरकार बनने के महीने भर के भीतर ही अपने पड़ोस में विदेश नीति को लेकर एक बड़ी जीत हासिल की।

मालदीव यात्रा के दौरान जिस तरह उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद जिस तरह से सकारात्मक द्विपक्षीय बातचीत हुई, उससे साफ है कि पीएम मोदी पिछली यूपीए सरकार के दौर में हुई बड़ी नीतिगत गलतियों को दुरुस्त करने में लगे हैं।

मालदीव ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी विभूषित किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव चीन के साथ अपने समुद्री समझौते को खत्म करने के कगार पर है। इस महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम से उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

THE HINDU

NATIONAL

Maldives confers highest civilian honour on Narendra Modi

Special Correspondent

COLOMBO, JUNE 08, 2019 16:22 IST
UPDATED: JUNE 08, 2019 23:56 IST

पड़ोसियों के सुख-दुख में सहभागी-भारत

पीएम मोदी ने 'सर्वप्रथम पड़ोस' की नीति के प्रति अपनी कटिबद्धता प्रकट करते हुए श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए भयावह आतंकी हमले के बाद वहां का दौरा किया। ऐसा करने वाले वे पहले विश्व-नेता थे।

इसके साथ ही, अब भारत की आपात एंबुलेंस सेवा श्रीलंका के सभी नौ प्रांतों में उपलब्ध है। भारत के इस सेवा और सहयोग भाव ने श्रीलंकाई लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है।

ईस्टर आतंकी हमले के बाद भारत की इस एंबुलेंस सेवा ने हालात से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

PM Modi becomes first world leader to visit Colombo church, pays homage to victims of Easter terror attacks in Sri Lanka

Prime Minister Narendra Modi made an unscheduled visit to the St Anthony's church to pay tributes to the victims of the horrific Easter Sunday terrorist attack that killed 258 people, including 11 Indians.

DNA Webteam | Jun 9, 2019, 09:20 PM IST

DNA HOME PHOTOS INDIA WORLD CUP ENTERTAINMENT WORLD BUSINESS TECHNOLOGY LIFESTYLE

Home > India

India-backed ambulance service in Sri Lanka expanded, now available across all provinces

The last phase of the project was launched in Ampara in the Eastern Province of Sri Lanka.

INDIA

By Express Web Desk | New Delhi | Updated: June 9, 2019 8:30:38 pm

'Together with you- come rain or shine': Sri Lankan President offers to hold umbrella for PM Modi

एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने दिखाई दिशा

पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को प्रभावी तरीके से रखते हुए सम्मेलन पर अमिट छाप छोड़ी तथा सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ साझी सहमति बनाने की अपील की।

बिश्केक में संपन्न हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को प्रायोजित करने, सहायता देने और धन मुहैया कराने वाले देशों को जिम्मेदार ठहराए जाने और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आह्वान किया।

सभी जानते थे कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था और वहां मौजूद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए यह और भी शर्मनाक था।

INDIA TODAY

PM Modi shames Pakistan at SCO Summit in presence of Imran Khan

Prime Minister Narendra Modi on Friday, without naming Pakistan, raised the issue of state-sponsored terrorism at the Shanghai Cooperation Organisation Summit in Bishkek and said that countries sponsoring, aiding and funding terrorism must be held accountable as he called for a global conference to combat the menace.

India Today Web Desk
New Delhi
June 14, 2019 UPDATED: June 14, 2019 17:24 IST

PM Modi deeply touched after Kyrgyzstan, Sri Lankan presidents personally hold umbrella for him

Recently, we saw the presidents of two nations personally holding an umbrella for PM Modi instead of security staff who usually are seen carrying them for world leaders. Well, Prime Minister Narendra Modi has been left humbled by the kind acts of the two presidents.

New Delhi, News Nation Bureau | Updated : 15 June 2019, 04:28 PM

जी–20 में पीएम मोदीः विश्व नेताओं से करीबी, सुखद भविष्य की ओर

वैश्विक नेताओं से व्यापक मुलाकात

पीएम मोदी जी-20 के चार सत्रों में उपस्थित रहे; इस दौरान उन्होंने 9 द्विपक्षीय बैठकों, 8 निजी मुलाकातों, 2 त्रिपक्षीय बैठकों – (अमेरिका-भारत-जापान तथा रूस-भारत-चीन) और ब्रिक्स नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया।

जी-20 के दौरान पीएम मोदी दुनिया के उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय और निजी मुलाकातें कीं। उनकी इतनी बैठकें विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती हैं।

उन्होंने कोबे में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने सिर्फ 2 दिनों में 25 कार्यक्रमों में भाग लिया!

पीएम मोदी ने सभी महाद्वीपों के नेताओं से मुलाकात की :
- अमेरिका (यूएसए और चिली)
- अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका)
- यूरोप (फ्रांस और जर्मनी)
- ऑस्ट्रेलिया
- पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया (चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम)
- पश्चिमी एशिया (सऊदी अरब)

THE ECONOMIC TIMES

PM Narendra Modi holds bilateral meetings with G20 leaders, stresses on jointly combating terrorism

BY ANI | UPDATED: DEC 02, 2018, 11.43 AM IST

livemint

PM Modi highlights 'importance of India' in trilateral meet with Trump, Abe

1 min read . Updated: 28 Jun 2019, 08:38 AM IST
PTI

- The discussion focused on how India, US and Japan can work together towards an open, stable Indo-Pacific region
- Today's meeting of the Japan-America-India Trilateral was a productive one, Modi tweeted

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए मुद्दों को वैश्विक समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर एक सत्र को संबोधित किया और रोग निवारण में भारत की पारंपरिक पद्धतियों के साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, 'आयुष्मान भारत' के बारे में बताया।

उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास का भी आह्वान किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्त्री-पुरुषों की समानता की आवश्यकता पर बल दिया; टेक्नोलॉजी के महत्त्व के बारे में बात की और विकास के लिए समाज द्वारा इसे अपनाने की जरूरत पर जोर दिया।

2014 में ब्रिसबेन में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन के मुद्दे को उठाया था और बताया था कि काले धन को वैश्विक स्तर पर खत्म करना क्यों जरूरी है। इस मुद्दे पर उन्हें व्यापक समर्थन मिला, यहां तक कि जी-20 के आधिकारिक बयान में भी इसका विशेष उल्लेख किया गया। तभी से यह एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंडा बना हुआ है।

2019 के जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ विश्व-स्तर पर एकजुट कार्रवाई किए जाने की जोरदार वकालत की।

2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी निरंतर इसी मुहिम में लगे हैं कि विश्वभर में एक ऐसी भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था हो जहां ईमानदार करदाताओं और व्यापारियों के हितों की रक्षा हो, न कि ऐसे गिने-चुने लोगों की, जो टैक्स नहीं चुकाते और अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए 'ओसाका ट्रैक' की चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। डेटा फ्री फ्लो और ई-कॉमर्स से जुड़ा 'ओसाका ट्रैक' विचार-विमर्श ओसाका के जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री आबे के खास एजेंडे में शामिल था।

आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री ने रखा जोरदार पक्ष

चाहे जी-20 हो, 'ब्रिक्स' हो या 'एससीओ', प्रधानमंत्री मोदी आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम का नेतृत्व करते रहे हैं। ओसाका जी-20 भी इससे अछूता नहीं रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतेरेस को आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा और विश्वास दिलाया कि भारत उसका पूर्ण समर्थन करेगा।

भारत और अमेरिका - एक सार्थक संवाद

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की मीडिया में काफी चर्चा हुई।

मोदी-ट्रम्प के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता सहज और सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने 5-जी, व्यापार, ईरान और सुरक्षा संबंधों जैसे विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा की।

द्विपक्षीय बैठक के अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प को विभिन्न सत्रों के दौरान, जी-20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज के दौरान, तथा लीडर्स लाउंज में भी कई बार घनिष्ठ अनौपचारिक चर्चा करते हुए देखा गया।

जी-20 नेताओं के रात्रिभोज में भाग लेने वालों ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की शाम काफी व्यस्त रही : उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन थे तो दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रम्प।

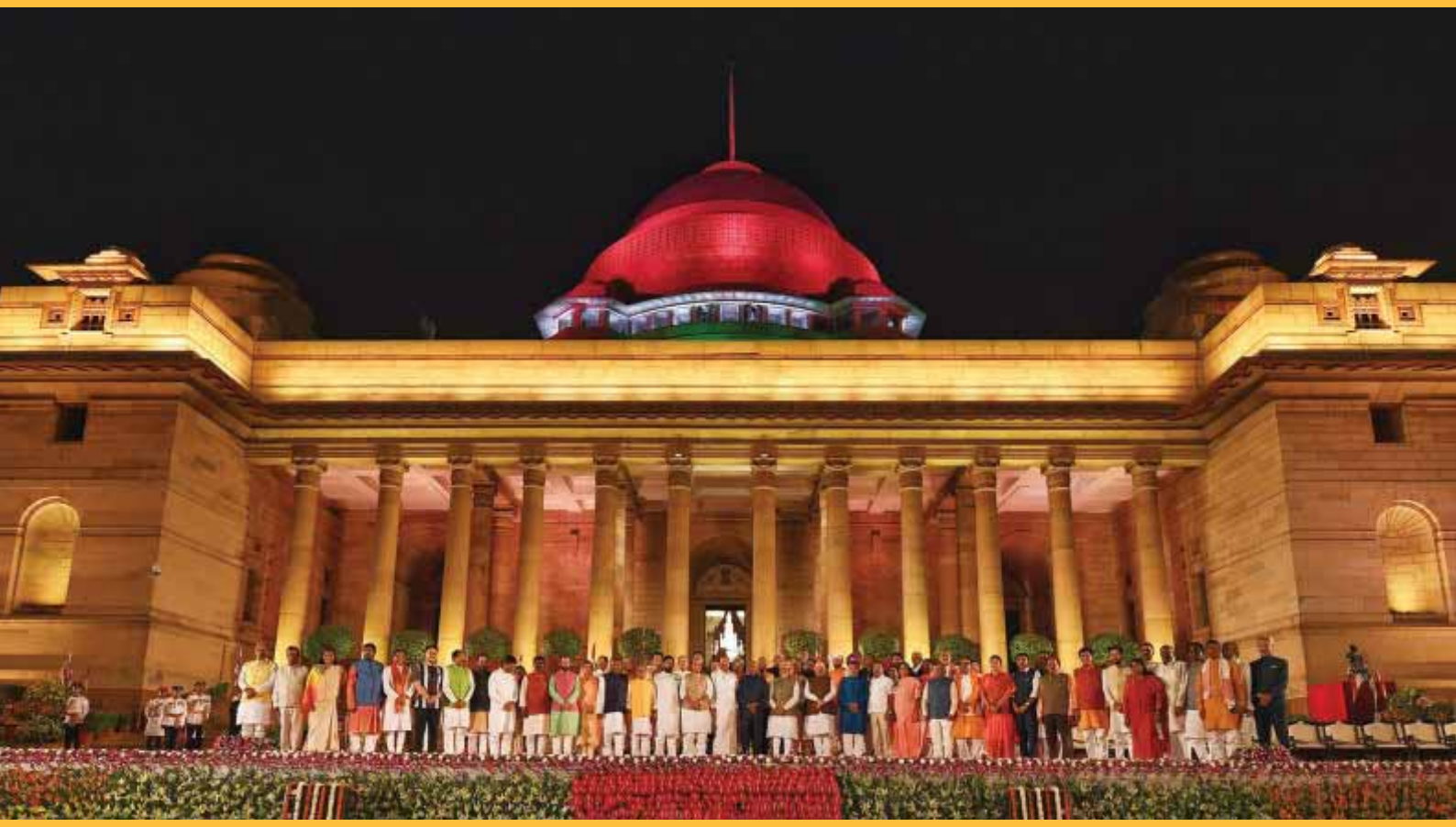

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

मुद्रक: कृति, नई दिल्ली 110 020